मुख्यमंत्री ने किया जी-20 डिजिटल इकोनामी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का शुभारंभ, गिनाईं खूबियां

यूपी में सभी सुविधाएं हुईं पारदर्शी : योगी

- डिजिटल टेक्नोलाजी के इस्तेमाल से प्रदेश के हर क्षेत्र में हो रहा परिवर्तन
- यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के पीछे भी डिजिटल प्लेटफार्म

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के होटल सेंट्रम में जी- 20 डिजिटल इकोनामी वर्किंग ग्रुप की बैठक का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश टेक्नोलाजी के उपयोग में सबसे आगे है। टेक्नोलाजी के उपयोग से ही यूपी में सभी सुविधाएं पारदर्शी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि टेक्नोलाजी का लाभ किस तरह लोगों को प्राप्त हो रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। उप्र में उचित मूल्य की 80 हजार दुकानें हैं। छह वर्ष पहले शिकायत होती थी कि इनके माध्यम से गरीबों को खाद्यान्न नहीं मिल पाता है। ई-पास मशीनों से उनकी निगरानी शुरू की गई। आज हम 15 करोड़ लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं। इतना ही नहीं हम सालाना 1200 करोड़ रुपये की बचत भी कर रहे हैं। कोरोना काल में प्रदेश में वैक्सीन लगाने में भी डिजिटल प्लेटफार्म की बड़ी भूमिका रही।

योगी ने कहा कि प्रदेश में 2.6 करोड़ किसानों को पीएम सम्मान निधि का लाभ, एक करोड़ निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, वृद्धजनों के बैंक खातों में पेंशन और एक करोड़ छात्रों के खातों में छात्रवृत्ति की रकम सीधे पहुंचाना डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण ही संभव हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल के 1.91 करोड़ छात्र-छात्राओं को यूनिफार्म, स्वेटर, बैग, जूते-मोजे खरीदने के लिए धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खातों में भेजी जाती है। सरकारी खरीद की नीति भी डिजिटल है। डिजिटल टेक्नोलाजी को आवश्यकता बताते हुए योगी ने कहा कि इसी उद्देश्य से हम प्रदेश के दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी उपलब्ध करा रहे हैं।

सोमवार को लखनऊ में जी-20 की डिजिटल इकोनामी वर्किंग ग्रुप की बैठक के उद्घाटन के अवसर पर (दाएं से बाएं) रेल, संचार व इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पाण्डेय और भाजपा सांसद राजीव चंद्रशेखर • एएनआइ

उद्योगों में डिजिटल नवाचार को दें बढ़ावा : महेंद्र नाथ

केंद्र सरकार के भारी उद्योग मंत्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि अर्थव्यवस्था के तमाम क्षेत्रों मे सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच के साथ ही नई तकनीकें भी सामने आ रही हैं जो कारोबार और सरकार के लिए महत्वपूर्ण हो गई हैं। रोबोटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तथा क्वांटम कंप्यूटिंग आदि इसके उदाहरण है। डिजिटल क्रांति भविष्य की अर्थव्यवस्था और मनुष्य व मशीन के बेहतर संबंध के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब निवेश का बड़ा हिस्सा जी-20 देशों से होगा, इसलिए आवश्यक है कि उद्योगों में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा दिया जाए।

निवेश सारथी से करेंगे निवेश की डिजिटल निगरानी : योगी

यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से उप्र को प्राप्त हुए 33 .50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इसके लिए भी हमें टेवनोलाजी को अपनाना पड़ा। प्रत्येक एमओयू की निगरानी के लिए निवेश सारथी के रूप में डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया गया। प्रदेश में ई-आफिस प्रणाली लागू होने का परिणाम है कि सरकारी विभागों के कामकाज में पारदर्शिता आई है।

लाभार्थियों को मिल रहा सौ प्रतिशत लाभ : राजीव चंद्रशेखर

केंद्रीय इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश की पिछली सरकारें टेक्नोलाजी के अभाव में पंगु बनी रहीं। एक प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कहा था कि हम दिल्ली से सौ रुपये देते हैं तो लाभार्थी तक 15 रुपये ही पहुंचते हैं। टेक्नोलाजी के जरिये हम उस चुनौती से पार पा चुके हैं। लाभार्थी को योजनाओं का सौ प्रतिशत लाभ मिल रहा है। यह दशक टेक्नोलाजी के क्षेत्र में बड़े निर्णयों वाला दशक होगा।

भारत के डिजिटल इकोनामी माडल को स्वीकार रही दुनिया : वैष्णव

- यूपीआइ प्लेटफार्म में किसी का एकाधिकार नहीं, सक्षम देशों में भी नहीं ऐसी व्यवस्था
- भारत के पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए अब तक 13 देशों ने किए एमओयू

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : रेल, संचार व इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत के सशक्त डिजिटल इकोनामी माडल की पूरी दुनिया सराहना कर रही है और कई विकसित देश भी अब इसे अपनाने पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर डिजिटल इंडिया की नई पालिसी के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से पेमेंट सिस्टम का एक मजबूत प्लेटफार्म खड़ा किया गया, जिसकी स्वीकार्यता तेजी से विश्व के कई देशों में बढ़ी है। अश्विनी वैष्णव सोमवार को जी-20 की डिजिटल इकोनामी वर्किंग ग्रुप की बैठक के उद्घाटन सत्र के बाद मीडिया से मुखातिब थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के कई देशों में डिजिटल इकोनामी का नियंत्रण कुछ सीमित कंपनियों के हाथ में है। इसके विपरीत हमनें पब्लिक फंड से पेमेंट सिस्टम का एक मजबूत और स्वस्थ प्लेटफार्म खड़ा किया। यूपीआइ का प्लेटफार्म तैयार किया, जिससे बैंक, स्टार्टअप, ई-कामर्स जुड़े लाखों छोटे से बड़े व्यापारी और 120 करोड़ लोग जुड़े। इस तरह के प्लेटफार्म में किसी व्यक्ति या किसी कंपनी का एकाधिकार नहीं हो सकता। इससे हर कोई जुड़ सकता है और दो रुपये से लेकर दो लाख तक का ट्रांजेक्शन कर सकता है। यूपीआइ में ट्रांजेक्शन का औसत समय सिर्फ दो सेकेंड है।

उन्होंने कोविड काल के दौरान विकसित किए गए कोविन पोर्टल का भी जिक्र किया कि इतने बड़े देश में 220 करोड़ वैक्सीन के डोज दो साल में लगे। उन्होंने बताया कि बहुत से देश हमारे माडल से प्रभावित हैं। अब तक 13 देशों ने एमओयू साइन किए हैं। सिंगापुर ने तो पूरी तरह से एकीकृत कर दिया है। कनाडा, जापान मैक्सिको ने भी रुचि दिखाई है।

गूगल ने अमेरिका को दी भारत का माडल अपनाने की सलाह : वैष्णव ने बताया कि गूगल ने अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक को चिट्ठी भी लिखी कि भारत का पेमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा है, जिसमें डेमोक्रेसी है। वह ऐसा ही सिस्टम अमेरिका में भी लागू करे।

लाजिस्टिक्स, कृषि में डिजिटल प्लेटफार्म : केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के डिजिटल प्लेटफार्म के सफल माडल को लाजिस्टिक्स, ई-कामर्स, एग्रीकल्चर में भी शीघ्र लेकर आएंगे जिससे कि छोटे से छोटा किसान भी इससे जुड़ सके।

डिजिटल दुनिया में अपने एकाउंट का ध्यान रखना होगा

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि साइबर क्राइम पर नियंत्रण के लिए तीन बड़े कदम उठाए गए हैं। लीगल, टेक्निकल और जागरूकता तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। यह एक सतत प्रक्रिया है। लोगों को भी जागरूक होना होगा। डिजिटल दुनिया में अपने एकाउंट का ध्यान रखना होगा।

संबंधित सामग्री ›› जागरण सिटी